



◆ वर्ष 25 ◆ अंक 108 ◆ पृष्ठ 8 ◆ रुद्रपुर (उधमसिंहनगर) ◆ बृहस्पतिवार ◆ 23 जनवरी 2025 ◆ मूल्य दो रूपया

✉ darpan.rdr@gmail.com 📞 9897427585 🌐 UTTARANCHAL DARPAN 🌐 www.uttaranchaldarpan.in

छोटी सरकार के लिए बरसे वोट

प्रदेश भर के 100 निकायों में कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ मतदान, अंतिम समय तक चला वोटरो को रिझाने का दौर

केसू/रुद्रपुर/उद संवाददाता। प्रदेश के 100 नगर निकायों में छोटी सरकार चुनने कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हुआ। प्रदेश भर में दोपहर तक लगभग 42 प्रतिशत मतदान हुआ चुका था। प्रदेश में कुल 1,516 मतसदान केंद्र और 3,394 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। इनमें 592 संवेदनशील और 412 अतिसंवेदनशील मतदेय स्थल शामिल हैं। मतदान को लेकर सुबह से ही पोलिंग बूथों पर लंबी लाइनें लगने लगीं। सुबह कोहरे के चलते मतदान धीमा हुआ। दिन चढ़ने के साथ ही मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। युवाओं से लेकर बुजुर्ग और दिव्यांग भी पूरे जोश के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंचे और लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर भारीदारी निभाई। प्रदेश भर में मतदान केंद्रों पर 18 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। चुनाव को देखते हुए पुलिस ने प्रदेश में 185 चेकिंग बैरियर स्थापित किए गए हैं। इनमें 117 बैरियरों पर सीसीटीवी



कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। 11 नगर निगमों में मेयर के लिए 72 प्रत्याशी मैदान में हैं जबकि 89 नगर पालिका, नगर पंचायतों में अध्यक्ष के 445 प्रत्याशी हैं। सभी निगम, पालिका, पंचायतों में वार्ड सदस्य/पार्षद के कुल 4,888 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस बार खास तौर पर बैलेट पेपर के रंगों में बदलाव किया गया है। मेयर प्रत्याशियों का बैलेट नीले, पार्षद और नगर पालिका व नगर पंचायत में वार्ड सदस्यों के सफेद बैलेट

पेपर रखे गए हैं। रुद्रपुर-निकाय चुनाव के लिए आज हुए मतदान में मतदाताओं में भारी उत्साह दिखाई दिया। सभी मतदान केंद्रों में प्रातः से ही मतदाताओं की लम्बी लाइनें लगनी शुरू हो गई थी। जिन्होंने अपने मतधिकार का प्रयोग कर प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटियों में बंद कर दिया। जो आगामी 25 जनवरी को होने वाली मतगणना के बाद खुलेगा। अनेक मतदान केंद्रों में मतदाता सूची में नाम न होने पर लोगों ने जमकर हंगामा भी किया।

वहीं एक मतदान केंद्रों के बाहर एक पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मतदान पच्ची के साथ पार्टी की प्रचार सामग्री बांटने पर लोगों ने भारी रोष जताया। रुद्रपुर के मेयर व 40 वार्डों के पार्षद पदों के लिए प्रातः 8 बजे से सभी मतदान केंद्रों पर मतदान प्रारम्भ हुआ। हजारों की संख्या में मतदाता मतदान शुरू होने से काफी पहले ही ठंड के बावजूद अपने मतदान केंद्रों में मतदान पच्ची के साथ लाईन लगाकर खड़े हो गये थे। मतदान के प्रति उनमें खासा उत्साह

देखने को मिल रहा था। नगर के ट्रांजिट कैम्प, आवास विकास, रविन्द्र नगर, रम्पुरा, भूत बंगला, फुलसुंगा फलसुंगी, पहाड़गंज, बाजार, आदर्श इन्द्रा बंगाली कालोनी, आदर्श कालोनी, नगर निगम, ओमैक्स कालोनी, जगतपुरा, संजय नगर, खेड़ा, दूधिया नगर, सिंह कालोनी, भूरानी आदि क्षेत्रों में बनाये गये मतदान केंद्रों में हजारों की संख्या में मतदाताओं ने अपनी पसंद के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया। सभी मतदान केंद्रों में

सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किये गये थे। मतदान केंद्रों में मोबाईल का प्रयोग प्रतिबंधित किया गया था। दोपहर तक करीब 42 प्रतिशत मतदान हुआ था। वहीं जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन भदौरिया तथा एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर मतदान व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया और ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। इससे पहले जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने ओमैक्स के पास फूल मंडी बूथ 156 में किया मतदान किया। वहीं भाजपा प्रत्याशी विकास शर्मा ने बगवाड़ा स्थित बूथ पर पत्नी के साथ पहुंचकर मतदान किया। कांग्रेस मेयर प्रत्याशी मोहन खेड़ा ने भूरानी स्थित बूथ पर मतदान किया। वहीं विधायक शिव अरोरा ने वार्ड न 31, मलिक कॉलोनी के आनंद पब्लिक स्कूल मतदान केंद्र (शेष पृष्ठ सात पर)



भूतबंगला में लाठीचार्ज, कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी घायल व्यापारी नेता को हिरासत में लिया

रुद्रपुर (उद संवाददाता)। मतदान के दौरान नगर निगम के वार्ड 20 भूतबंगला स्थित पोलिंग बूथ पर फर्जी मतदान कराने को लेकर बखेड़ा हो गया। इस दौरान पुलिस ने हंगामा कर रहे कुछ लोगों पर लाठी चार्ज कर दिया जिससे वहां अफरा तफरी मच गयी। लाठीचार्ज में कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी परवेज कुरैशी घायल हो गये। उन्हें जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाये हैं। उधर विधायक शिव अरोरा का कहना था कि फर्जी वोटिंग के साथ-साथ आपराधिक किस्म के आये लोग बूथ के चक्कर करने के प्रयास में थे। जिन्हें पुलिस द्वारा खदेड़ दिया गया। पुलिस की कार्रवाई में वार्ड 20 के कांग्रेस



प्रत्याशी परवेश कुरैशी के घायल होने की सूचना पर पूर्व मंत्री एवं किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ ने अस्पताल पहुंचकर घायल का हाल जाना और भाजपा पर गंभीर आरोप भी लगाये। जानकारी के

अनुसार सुबह करीब दस बजे भूतबंगला वार्ड नं. 20 में मतदान चल रहा था। इसी दौरान वहां किसी बात को लेकर हंगामा हो गया। मौके पर कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी परवेज कुरैशी जब पुलिस से उलझा तो

पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया जिससे वहां अफरा तफरी मच गयी। घायल परवेज कुरैशी को जिला अस्पताल भर्ती कराया। परवेज कुरैशी का कहना है कि वह अपने परिचितों को वोट डलवाने के लिए बूथ पर आये थे, इसी दौरान पुलिस ने उन पर हमला कर दिया। वही हंगामे की सूचना पर विधायक शिव अरोरा भी मौके पर पहुंच गये। उन्होंने कहा कि कुछ लोग फर्जी वोटिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं इसे बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। उन्होंने प्रशासन से कहा कि जो भी फर्जी वोट डालने की कोशिश कर रहा है उस पर सख्त कार्रवाई करें। शिव अरोरा ने कहा कि अपराधिक किस्म के लोग यहां पर बूथ को चक्कर करने की कोशिश कर रहे थे और फर्जी (शेष पृष्ठ सात पर)

रुद्रपुर (उद संवाददाता)। आचार संहिता का उल्लंघन करने की शिकायत पर पुलिस ने ट्रांजिट कैम्प क्षेत्र के एक वार्ड से लघु उद्योग व्यापार मण्डल अध्यक्ष संजीव गुप्ता को हिरासत में ले लिया। जानकारी के मुताबिक ट्रांजिट कैम्प क्षेत्र



के वार्ड नं. 10 में पोलिंग बूथ के बाहर आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत मिलने पर पुलिस ने मौके से संजीव गुप्ता को हिरासत में ले लिया। मामले में संजीव गुप्ता का कहना था कि भाजपा के कुछ लोग बूथ के पास लिफाफे बांट रहे थे, जिसमें भाजपा प्रत्याशी का फोटो और चुनाव चिन्ह छपा (शेष पृष्ठ सात पर)

प्रत्याशी का बैनर उतार रहे युवक की करेंट से मौत

देहरादून (उद संवाददाता)। जौलीग्रांट में निकाय चुनाव के दौरान हादसा हो गया। दुर्गा चौक भानियावाला के पास छत से एक प्रत्याशी का बैनर उतारते हुए एक युवक 33 केवी लाइन की चपेट में आ गया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, घटना सुबह दस बजे करीब हुई। युवक छत की दूसरी मंजिल से चुनावी बैनर उतारने गया। छत का एक कोना 33 लाइन को छू रहा था। जैसे ही वह बैनर उतारने लगा एक तेज धमाका हुआ और युवक छत पर ही गिर पड़ा। घटना के बाद मौके पर काफी भीड़ लग गई। लोगों ने एंबुलेंस को फोन किया। युवक के शव को सीएचसी डॉईवाला ले जाया गया। चौकी इंचार्ज सुमित चौधरी ने कहा कि 33 केवी लाइन की चपेट में आने से अटुरवाला के युवक की मौत हुई है। जिसका नाम मनोज पंवार उम्र 26 बताया गया है।

डीएम और एसएसपी ने परखी व्यवस्थायें वोटरो को पैसे बांटने पर हंगामा

रुद्रपुर। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने फूल मंडी बूथ नम्बर 156 में अपने मत का प्रयोग किया। उसके उपरांत जिला निर्वाचन अधिकारी ने फूल मंडी बूथ संख्या 155, 156, 157, 158 व लालपुर नगर निकाय के किसान इंटर कालेज लालपुर के बूथ संख्या-1, 2, 3, 4 का स्थलीय निरीक्षण कर मतदान का जायजा लिया। उन्होंने



रिटनिंग आफिसर, सहायक रिटनिंग आफिसर को बूथ पर लगी लाईन को व्यवस्थित करने के साथ ही दिव्यांग,

बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं व छोटे बच्चों को लेकर आयी महिलाओं को प्राथमिकता से मतदान कराने के निर्देश दिये। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार दिनेश कुटौला, रिटनिंग आफिसर लालपुर सुशील कुमार, सहायक रिटनिंग आफिसर विशाल प्रसाद, जोनल मजिस्ट्रेट आदि मौजूद थे। वहीं एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने भी कई मतदान केंद्रों का (शेष पृष्ठ सात पर)

वोटरो को पैसे बांटने पर हंगामा

रुद्रपुर (उद संवाददाता)। ट्रांजिट कैम्प क्षेत्र के वार्ड नंबर दस में बुधवार देर रात वोटरो को पैसे बांटने को लेकर हंगामा हो गया। लोगों ने एक व्यक्ति को मौके पर पकड़ लिया। जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रांजिट कैम्प की एक बस्ती में बीती रात कुछ लोग वोटरो को पैसे बांट रहे थे, जिस पर लोगों ने हंगामा कर दिया। पैसे बांट रहे एक व्यक्ति को लोगों ने पकड़ लिया। लोगों (शेष पृष्ठ सात पर)



टारगेट क्षमता के मामले में दिल्ली, भोपाल के बराबर में खड़ा होने जा रहा है। यह स्थिति उत्तराखण्ड के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तमाम राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाएं उत्तराखण्ड में अब सफलतापूर्वक कराई जा सकती हैं।

के निर्णय से साहसिक खेलों के लिए अवस्थापना सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। राज्य की भौगोलिक स्थिति साहसिक खेलों को अनुकूल है, जिसको देखकर राज्य के विभिन्न हिस्सों में रोमांच के शौकीन लंबे समय से ट्रैकिंग, राक क्लाईंबिंग, स्कीइंग और रिवर राफ्टिंग के लिए आ रहे हैं। श्री के. एस चौहान ने बताया कि इस माह उत्तराखण्ड में दिनांक 28 जनवरी से प्रारम्भ हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हम सभी के लिए एक गौरव का क्षण है। उत्तराखण्ड राज्य की झांकी का निर्माण स्मार्ट ग्राफ आर्ट एडवर्टाईजिंग प्रा0लि0 के निदेशक श्री सिद्धेश्वर काजूा द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखण्ड के लोक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया जायेगा।





गुरु माँ एडवांस् डेन्टल क्लीनिक

WORLD-CLASS DENTAL CARE NOW IN YOUR CITY

रूट कैनाल विशेषज्ञ

डेन्टल इम्प्लांट

टेढ़े-मेढ़े दांतों का इलाज







डॉ. ऑचल हींगरा
 बी.डी.एस, एम.डी.एस. एंडोडोन्टिस्ट
 रूट केनाल स्पेशलिस्ट, कॉस्मेटिक डेन्टिस्ट
 सर्टिफाइड एस्थैटिक डेन्टिस्ट

Guru Maa Advanced Dental Care "A Multi Speciality Dental Clinic"
 १ प्लॉट नं 1, सिविल लाइन्स, रुद्रपुर | ☎ 7452880018, 05944-245666



उत्तरांचल दर्पण सम्पादकीय

सत्यम् शिवम् सुन्दरम्



आजीवन कारावास की सजा

कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ बलात्कार और फिर हत्या के मामले में अदालत ने दोषी को आजीवन करावास की सजा सुनाई है। इससे निश्चय ही पीड़ित परिवार और न्याय की मांग कर रहे लोगों को राहत मिली है। इससे बलात्कार जैसे मामलों में त्वरित सुनवाई और फैसले की उम्मीद भी जगी है। पिछले वर्ष अगस्त में अस्पताल के सम्मेलन कक्ष में प्रशिक्षु डाक्टर का शव मिला था। जांच में पता चला कि उसके साथ बलात्कार हुआ था। इसे लेकर काफी हंगामा शुरू हो गया। शुरूआती छानबीन में ही आरोपी की पहचान कर ली गई थी। फिर देश भर के डाक्टर आंदोलन पर उतर आए, अनेक शहरों में नागरिक संगठनों ने भी विरोध जताया था। कोलकाता में चिकित्सक और नागरिक लगातार इस घटना के विरोध में आंदोलन चलाते रहे। तब इस मामले की जांच सीबीआइ को सौंप दी गई थी। जांच में तेजी लाई गई और आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले। उसी आधार पर अदालत ने फैसला सुनाया है। दो महीने से भी कम समय में सुनवाई पूरी करते हुए अदालत फैसले तक पहुंच गई। इससे जाहिर है कि अगर जांच एजंसियां तत्परता दिखाएं और अदालतें बलात्कार और हत्या जैसे मामलों में संजीदगी से सुनवाई करें, तो न्याय जल्दी मिल सकता है। बलात्कार के मामलों में अक्सर देखा जाता है कि दोष सिद्ध नहीं हो पाता। पीड़िता और उसका परिवार न्याय से वंचित रह जाते हैं। बलात्कार के मामलों में दोषसिद्धि की दर बहुत कम है। इसलिए भी ऐसे अपराध करने वालों का मनोबल तोड़ना कठिन होता है। दिल्ली में निर्भया कांड के बाद महिला अपराध संबंधी कानूनों को काफी सख्त बना दिया गया। बलात्कार के मामले में जांच और सुनवाई में तेजी लाने का प्रावधान किया गया। मगर उसका भी कोई अपेक्षित असर नजर नहीं आता। बलात्कार के मामले हर वर्ष कुछ बड़े हुए ही दर्ज होते हैं। आरजी कर अस्पताल की घटना को भी वहां के प्रशासन ने प्राथमिक तौर पर दबाने–छिपाने का ही प्रयास किया था। अगर वहां के चिकित्सा कर्मियों और जागरूक नागरिकों ने आंदोलन तेज न किया होता, तो शायद उस पर भी इतनी जल्दी फैसला न आ पाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने उस आंदोलन के दबाव में आकर ही मामले की निष्पक्ष जांच में सहयोग किया। पीड़ित परिवार ने किसी भी तरह का मुआवजा लेने से इनकार कर दिया था। उसकी मांग थी कि न्याय मिलना चाहिए। सीबीआइ और दूसरे पक्षकार दोषी को फांसी की सजा की मांग कर रहे थे, मगर अदालत ने बहुत ही सुलझे हुए ढंग से आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरजी कर प्रशिक्षु चिकित्सक हत्या मामले में अपनाई गई जांच प्रक्रिया और सुनवाई एक नजीर है कि कैसे इस तरह के मामलों को निपटया जाना चाहिए। ऐसे मामले अक्सर जांच में लापरवाही बरतने और आरोपी के साथ मिलीभगत के कारण बिना उचित न्याय के खत्म हो जाते हैं। जिन मामलों में रसूखदार लोग आरोपी होते हैं, उनमें निष्पक्ष जांच की संभावना कम ही होती है। अदालतें चूँकि जांच और सबूतों के आधार पर ही किसी निर्णय पर पहुंचती हैं, मगर जब वही ठीक से नहीं पेश किए जाते, तो मामले धुंधलके में खो जाते हैं। बलात्कार के मामलों में अक्सर उन महिलाओं को न्याय नहीं मिल पाता, जिनके पास योग्य वकील कर पाने का पैसा और प्रशासन पर दबाव बना सकने की क्षमता नहीं होती। इसमें सरकारों की दृढ़ इच्छाशक्ति का होना भी जरूरी है।

खिलाड़ियों को बेहतर भोजन व आवास के लिए होटल स्वामियों को दिए निर्देश

हल्द्वानी (उद संवाददाता)। 38 वे राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के संबंध में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में नैनीताल डिस्टिक कोऑपरेटिव बैंक सभागार में खिलाड़ियों के आवास एवं भोजन के लिए होटल स्वामियों के साथ बैठक की गई। बैठक में आंगतुक खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं देने हेतु होटल स्वामियों



को निर्देश दिए गए। थॉमस कुक के प्रतिनिधियों को होटल स्वामियों के साथ समन्वय स्थापित कर खिलाड़ियों को सुव्यवस्थित ढंग से ठहराने के निर्देश दिए गए। होटल में स्थानीय उत्पाद प्रदर्शित किए जाने हेतु महाप्रबंधक जिला उद्योग विभाग को निर्देश दिए गए। हर होटल में पर्यटन संबंधित सामग्री को भी रखा जाएगा ताकि खिलाड़ी नैनीताल जिले एवं राज्य के पर्यटक स्थलों की जानकारी प्राप्त कर सकें।

गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों के आयोजन की बनाई रूपरेखा

अल्मोड़ा (उद संवाददाता)। गणतंत्र दिवस 2025 के आयोजन के संबंध में जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडेय की अध्यक्षता में एक बैठक कलैक्ट्रेट में सम्पन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने कार्यक्रम के आयोजन को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि गणतन्त्र दिवस के अवसर पर प्रभात फेरी का आयोजन प्रातः 7 बजे से नन्दादेवी प्रांगण से मुख्य बाजार होते हुए चौधानपाटा तक किया जायेगा। इसके लिए उन्होंने मुख्य शिक्षा अधिकारी को आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए। 26 जनवरी के दिन प्रातः 9:30 बजे सभी सरकारी, अर्धसरकारी कार्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों में ध्वजारोहण किया जायेगा तथा राष्ट्रीय गान एवं संकल्प पढ़ा जायेगा । बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि समस्त उपजिलाधिकारी जनपद अल्मोड़ा में अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों, सैन्य विधवाओं, उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को ध्वजारोहण कार्यक्रम में आमन्त्रित करें। गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहरण एवं पुलिस परेड का आयोजन 10:30 बजे से 01 बजे तक पुलिस लाईन में किया जायेगा। इस अवसर पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, लैप्रोसी मिशन करबला एवं नारी निकेतन बख में फल वितरण किया जायेगा। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शाशनी, अपर जिलाधिकारी सीएस मर्तोलिया, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ आरसी पंत, उपजिलाधिकारी सदर संजय कुमार, पुलिस उपाधीक्षक विमल प्रसाद समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

कर्मचारियों की खुशहाली के परिणाम?

केंद्रीय मंत्रीमण्डल ने आठवें वेतन आयोग के गठन का फैसला लिया है। इसकी सिफारिशें लागू होने पर 45 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन बढ़ जाएंगे। 1 जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग का कार्यकाल शुरू होगा। इस आयोग के परिणाम से उम्मीद हैं कि न्यूनतम मूल वेतन 18000 से 51000 हो जाएगा। इस नई वेतनवृद्धि से अर्थव्यवस्था पर 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आने का अनुमान है। केंद्र में नई सिफारिशों के लागू होने के बाद प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के वेतन में भी वृद्धि कर दी जाती है। केंद्रीय कर्मचारियों की इस खुशहाली से जहां सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को गति मिलने की उम्मीद की जा रही है, वहीं इससे महंगाई बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। समाज में विभिन्न तबकों के बीच आयगत असमानता की खाई और चौड़ी होगी। इससे न केवल विकास के रास्ते में मुश्किलें खड़ी होंगी,बल्कि जो लोग क्रयशक्ति की दृष्टि से हाशिए पर हैं,उन्हें जीवन–यापन में और कठिनाईयां पेश आ सकती हैं। गोया, कर्मचारियों को खुशहाली के ये उपहार सरकारी खजाने के लिए सातवें वेतन आयोग की तरह निराशाजनक साबित हो सकते हैं। क्योंकि इससे राजकोश पर सालाना करीब 2 लाख करोड़ का अतिरिक्त भार पड़े गा। जाहिर है , इस बोझ से अर्थव्यवस्था की गति और धीमी ही पड़ेगी। इन वेतनमााओं का अनुकरण भविष्य मेंरेलवे, बैंक और राज्य सरकारों को भी करना होगा। गोया, इनमें भी विकास की गति धीमी पड़ना तय है। जबकि ये राज्य अपना खर्च अपनी आय के स्रोतों से उठाने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे ही विशंगतियों के चलते गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती हैं। फिलहाल भारत सरकार 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में 35 किलो अनाज उपलब्ध करा रही है। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक तय समय सीमा में वेतन आयोग गठित होता है। आयोग की सिफारिशों के मुताबिक भेतन–भत्तों में बढ़ोत्तरी भी की जाती है। ताकि उन्हें,बढ़ती महंगाई और बदली परिस्थितियों के परिदृश्य में आर्थिक कठिनाईयों का सामना नहीं करना पड़े। इसीलिए 1946 में जो पहला वेतन आयोग बना था,उसने 35 रूपए मूल

वेतन तय किया था। 1959 में दूसरे आयोग ने इसे बढ़ाकर 80 रुपए किया। 1973 में तीसरे ने 260,चौथे ने 1986 में950 किया। वहीं पांचवें आयोग ने इसे एक साथ तीन गुना बढ़ाकर 3050 रुपए कर दिया। छठे ने इसे बढ़ाकर 7730 रुपए किया, जबकि छठे वेतन आयोग ने मूल वेतन में 20 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की थी। किंतु डॉ मनमोहन सिंह सरकार ने अतिरिक्त उदारता बरतते हुए, इसे लागू करते समय दोगुना कर दिया था। सातवें आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप केंद्र सरकार के कर्मचारियों का अधिकतम वेतन ढाई लाख रुपए और न्यूनतम वेतन 18000 रुपए हो गया है। अब आठवें वेतन आयोग में न्यूनतम मूल वेतन 18000 रुपए से बढ़कर 51000 रुपए हो सकता है ? इस तरह से ये वेतन सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों से ज्यादा हो जाएगा। गोया, इस विशंगति से इनके अहम् को ठेस लगना स्वाभाविक है। लिहाजा संसदों द्वारा वेतन–भत्तों को बढ़ाने की मांग उठना लाजिमी है। आगे–पीछे सरकार को यह मांग भी मानना पड़ेगी। इन वेतन वृद्धियों से केंद्र सरकार के 45 लाख वर्तमान कर्मचारियों और 65 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों को तो लाभ मिलेगा ही सशस्त्र बलों को भी मिलेगा। इन सिफारिशों के लागू होने के बाद अगले दो–ढाई साल तक सरकार इससे उपजने वाली आर्थिक खाई में संतुलन बिठाने में ही लगी रहेगी। नए औद्योगिक विकास और खेती को किसान के लिए लाभ का धंधा बनाए जाने के उपायों से बुरी तरह पिछड़ जाएगी। इन वेतन वृद्धियों से महंगाई का ग्राफ भी उछलेगा। जिसका सामना न केवल किसान–मजदूर,बल्कि असंगठित क्षेत्र से आजीविका चला रहे हर व्यक्ति को करना पड़ेगा। हालांकि सरकार को यह मुगालता है कि वेतन–वृद्धि से निवेश के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी। नतीजतन घरेलू मांग बढ़ेगी और रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा होंगे। कुल मिलाकर देश की माली सूरत ‘शाइनिंग इंडिया’ में बदल जाएगी। यह स्थिति केवल सरकारी कर्मचारियों के अनुकूल रहेगी। इस क्षेत्र में भी सविदा आधारित नियुक्त कर्मचारी और दैनिक वेतन भोगियों को इस अनुपात में लाभ नहीं दिया जाएगा। यही नहीं वेतन बढ़ा देने से न तो कर्मचारियों में कार्यकुशलता

और जबाबदेही देखने में आई, बल्कि इसके उलट इसी अनुपात में भ्रष्टाचार और बढ़ गया। जिस न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के विचार को प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ाने का दावा किया था, वे सातवें वेतनमान के लागू होने के बाद ही ध्वस्त हो गए थे। इसके विपरीत बढ़ी तनखाहों के अनुपात में भ्रष्टाचार भी बढ़ता देखा गया है। सरकार को इस बाबत यह सोचने की जरूरत है कि देश में मौजूद कुल नौकरियों में से करीब 8. 5 प्रतिशत संगठित क्षेत्र में हैं। शेष असंगठित क्षेत्रों में हैं। जहां न तो वेतन–भत्तों में समानता है और न ही सामाजिक सुरक्षा की गारंटी है। देश की सबसे बड़ी आबादी कृषि और कृषि आधारित मजदूरी पर आश्रित है। लेकिन इन दोनों ही वर्गों की आमदनी की कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में जिन राज्यों को सूखा व ओलावृष्टि का सामना करना पड़ेगा, उन्हें फसल उत्पादन से जुड़े वर्गों की रक्षा करना मुश्किल होगा ? जबकि सरकारीकर्मियों की नौकरी में स्थायित्व है। जवाबदेही की कोई गारंटी नहीं है। स्वास्थ्य बिगड़ने और पर्यटन पर जाने पर भी वेतन मिलते हैं। बावजूद भ्रष्टाचार, कदाचरण एवं निरंकुशता अपनी जगह बदस्तूर हैं। जबकि इन्हीं स्थितियों में असंगठित क्षेत्र के लोगों का काम प्रभावित होता है, नतीजतन उन्हें आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। इसी कारण देखने में आ रहा हैं कि मझोले और लघु कृषकों की ज्यादातर जमीनें सरकारी कर्मचारी खरीदते जा रहे हैं। रियल स्टेट और शेयर बाजार में भी इनकी भूमिका बढ़ रही है। यह स्थिति चिंताजनक है। इन सब हालातों को ही दृष्टिगत रखते हुए स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश की थी कि हर फसल पर किसान को लागत से डेढ़ गुना दाम दिया जाए। डॉ मनमोहन सिंह की सरकार ने तो इसे नजरअंदाज किया ही,नरेंद्र मोदी की राजग सरकार ने भी इसे लगभग खारिज किया हुआ है, जबकि जरूरी था कि सरकार खेती–किसानी से जुड़े लोगों की आमदनी बढ़ाने के उपाय तो करती ही, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत करोड़ों लोगों की आय बढ़ाने के तरीके भी तलाशती ? दरअसल केंद्र सरकार और उसके रहनुमाओं को यह भ्रम है कि महज केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि से बाजार में तेजी आ जाएगी। सरकार को

उम्मीद है कि इस राशि को जब कर्मचारी खर्च करेंगे तो भवन,वाहन, इलेक्ट्रोनिक एवं संचार उपकरणों की बिक्री बढ़ेगी। लेकिन सरकार को यहां विचार करने की जरूरत है कि केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या बहुत सीमित है और इनमें से ज्यादातर सभी आधुनिक सुविधाओं से अटे पड़े हैं। अधिकांश कर्मचारियों के पास हर बड़े शहर में आवास हैं और परिवार के हरेक सदस्य के पास वाहन सुविधा है। वैभव और विलास का यह जीवन उन्हें उत्तरदायित्व से विमुख कर रहा है। बावजूद सरकारी कर्मियों को उत्तरदायी बनाने पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा ? एक वक्त समयबद्ध सेवा सुनिश्चित करने का कानून बनाने की बात उठी थी, लेकिन वह आई–गई हो गई। जबकि इसे कानून बनाने के अजेंडे में लाने की जरूरत है। कर्मचारियों को कार्य–प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कृत व पदोन्नत करने के उपाय किए जाएं तो जवाबदेही सुनिश्चित हो सकती है। बढ़े हुए वेतन के साथ भ्रष्टाचार मुक्त लोकदायित्व की अपेक्षा तो की ही जानी चाहिए ? क्योंकि अंततः कर्मचारियों को जो वेतन भत्ते मिलते हैं,उस धन का निर्माण कृषि, प्राकृतिक संपदा का दोहन, पशुधन से मिलने वाली राशि और उद्यमियों से मिलने वाले कर ही हैं। इसलिए समूची प्रशासनिक व्यवस्था को समाज के प्रति उत्तरदायी बनाए जाने के साथ–साथ पारदर्शी भी बनाया जाना जरूरी था, लेकिन सरकार कर्मचारियों को नाराज करने का जोखिम उठाना नहीं चाहती। चुनांचे इस इजाफे से अर्थव्यवस्था को बहुत बड़े पैमाने पर गति मिलने वाली नहीं है। तत्काल मिलती भी है तो वह लंबी काल अवधि तक टिकने वाली नहीं है। यह तो तभी संभव है,जब उन असंगठित क्षेत्रों के समूहों की भी आमदनी बढ़े,जो देश की बड़ी आबादी का हिस्सा हैं और क्रयशक्ति के लिहाज से हाशिए पर हैं। मगर हाशिए पर पड़े इन लोगों पर निगाह ही नहीं डाली जा रही है, शायद इस आशंका से की कहीं पूंजीवादी प्राथमिकताओं को बदलने की जरूरत न पड़ जाए ? लिहाजा कर्मचारियों को खुशहाल बनाए जाने की ये सौगातें आम आदमी को राहत पहुंचाने वाली नहीं हैं।
प्रमोद भार्गव,लेखक वरिष्ठ साहित्यकार और पत्रकार हैं।

राज्यपाल के समक्ष किया शोध कार्य की प्रगति पर प्रस्तुतीकरण

देहरादून (उद संवाददाता)। बुधवार को राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) के समक्ष श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एन के. जोशी ने“वन यूनिवर्सिटी–वन रिसर्च” योजना के तहत चल रहे शोध कार्य की प्रगति पर प्रस्तुतीकरण दिया। श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा “आधुनिक परिदृश्य में भारतीय प्राच्य ज्ञान परंपरा” विषय पर शोध किया जा रहा है। प्रस्तुतीकरण के दौरान कुलपति ने बताया कि शोध पत्र को 7 खण्डों, प्राच्य विज्ञान एवं प्राचीन गणित, इतिहास

संस्कृति एवं राजनैतिक विचार, आयुर्वेद एवं योग, अर्थशास्त्र एवं प्रबंधन, पर्यावरण, दर्शन एवं शैक्षिक चिंतन और बहुविषय में विभाजित किया गया है। शोध पत्र का उद्देश्य प्राचीन ज्ञान तथा आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मध्य समन्वय स्थापित किया जाना है, इसके साथ–साथ हमारे समृद्ध ज्ञान को आधुनिक परिपेक्ष्य में पुनर्स्थापित करना और हमारे प्राच्य ग्रन्थों में निहित ज्ञान को संरक्षित किया जाना है। इस दौरान उन्होंने विस्तृत रूप से सभी खण्डों में निहित शोध प्रबंध के बारे में अवगत कराया। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय द्वारा किए गए शोध

कार्य की सराहना करते हुए कहा कि हमारा प्राचीन ज्ञान हमारी अमूल्य धरोहर है, लेकिन इसके महत्व और उपयोगिता से बहुत कम लोग परिचित हैं। यह शोध प्रबंध विज्ञान, गणित, आयुर्वेद, योग, खगोलशास्त्र और राजनीति जैसे प्राचीन भारतीय ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों को वैश्विक स्तर पर एक अमूल्य धरोहर के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इन ज्ञान शाखाओं ने न केवल हमारी संस्कृति को समृद्ध किया है, बल्कि इनकी वैश्विक प्रासंगिकता भी प्रमाणित हुई है। राज्यपाल ने कहा कि इस समृद्ध ज्ञान को संरक्षित

कर, इसे वैश्विक विकास, सांस्कृतिक सशक्तीकरण और वैज्ञानिक अनुसंधान में समाहित करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हमारा प्राचीन ज्ञान जो हमारी धरोहर है जिसके बारे में प्रत्येक भारतीय को जानकारी होना जरूरी है। शोध के माध्यम से निकले निष्कर्ष से भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रचार–प्रसार होगा। राज्यपाल ने शोध टीम के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर अपर सचिव श्रीमती स्वाति एस. भदौरिया, प्रो. कल्पना पंत, संयुक्त निदेशक सूचना डॉ. नितिन उपाध्याय उपस्थित रहे।

पहाड़ से मैदान तक छाए बादल कई जिलों में बारिश के आसार

देहरादून। उत्तराखंड में आज मौसम फिर बदलेगा। दिन की शुरुआत पहाड़ में बादलों के साथ हुई। वहीं, मैदानी इलाकों में हल्का कोहरा छाया हुआ है। आज पर्वतीय जिलों के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान देहरादून समेत उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। जबकि इन जिलों के कुछ हिस्सों में बिजली चमकने के भी आसार हैं। बीते कुछ दिनों से मौसम सुहावना होने से ठंड से राहत मिली है। उधर देहरादून के मौसम ने बुधवार को चार दिन बाद फिर नया रिकॉर्ड बनाया। यहां का अधिकतम तापमान सामान्य से छह डिग्री बढ़ोत्तरी के साथ 25.9 डिग्री दर्ज किया गया। इससे पहले साल 2020 में इस दिन दिन का अधिकतम तापमान 23.6 डिग्री रहा था। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मौसम के बदले पैटर्न और विंटर सीजन की बारिश में कमी के चलते तापमान में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। आंकड़ों पर नजर डाले तो प्रदेश भर में दिन के साथ रात के न्यूनतम तापमान में भी इजाफा देखने को मिला।



































के घरों, सरकारी संस्थाओं और इंडस्ट्री उपभोक्ताओं में लगाया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य यह है कि विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी सबसे पहले स्वयं स्मार्ट मीटर की तकनीकी बारीकियों को समझें और उसकी खामियों को सुधारें, जिससे आगे चलकर उपभोक्ताओं को निर्बाध सेवाएं प्रदान की जा सकें। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह प्रीपेड मीटर नहीं बल्कि पोस्ट पेड मीटर हैं, जिसका बकायदा बिल आएगा। लेकिन यह सफाई आते आते काफी देर हो चुकी थी और चुनाव में कांग्रेस के लिए यह मुद्दा संजीवनी बनता नजर आया। आज मतदान की प्रक्रिया के दौरान भी जगह जगह लोगों की नुबान पर स्मार्ट मीटर ही छाया हुआ था। बहरहाल स्मार्ट मीटर का मुद्दा चुनाव में क्या रंग लायेगा यह तो 25 जनवरी को ही साफ होगा, लेकिन संयासी हलकों में माना जा रहा है कि अगर बड़ा उलट फेर हुआ तो इसके पीछे स्मार्ट मीटर ही मुख्य मुद्दा माना जायेगा।

चुनाव में जनता इतिहास रचेगी। भाजपा रिकार्ड मतों से निगम में हैट्रिक बनायेगी। उन्होंने बूथों पर मतदान के लिए पहुंचे देवतुल्य मतदाताओं का आभार भी व्यक्त किया। कहा कि जनता के आशीर्वाद से

हल्द्वानी/रूद्रपुर (उद संवाददाता)। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक योगेन्द्र रावत ने जनपद नैनीताल और उधमसिंहनगर के विभिन्न मतदान केंद्रों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। कमिश्नर दीपक रावत एवं डीआईजी योगेन्द्र रावत ने हल्द्वानी व रूद्रपुर में स्थापित कई मतदान केंद्रों पर



रूरपुर को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना पूरा किया जायेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में शहर का चहुमुखी विकास होगा और कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो जनभावनाओं के विपरीत हो।



मिला। मतदान केन्द्रों में सूची में नाम न होने के कारण मतदान करने से वंचित मायूस लौट रहे कई मतदाताओं की आंखों से आंसू छलकते भी देखे गये।

रुद्रपुर। मतदान के दौरान मतदान केन्द्र के बाहर मतदान करने जा मतदाताओं को एक पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं द्वारा मतदाता पर्ची व साथ अपने प्रत्याशी व पार्टी के चुनाव प्रचार की सामग्री नथी किये जा पर विपक्षी दल के लोगों ने जमकर हंगामा किया। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस टीम भी मौके पर आ पहुँची और उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुए ऐसा न करने की सख्त हिदायत दी। बताया जा रहा है कि ट्रांजिट कैम्प में खड़ी वाली गली के बाहर एक पार्टी के लगे कुर्सी मेज पर कार्यकर्ताओं द्वारा मतदान करने जाते मतदाताओं को मतदान पर्ची के साथ अपने प्रत्याश व पार्टी के चुनाव प्रचार की सामग्री नथी कर दी जा रही थी। इसकी भनक लगते ही विपक्षी लोगों ने आपत्ति की तो दोनों पक्षों मध्य तीखी तकरार होने लगी। मामले की जानकारी मिलने पर ट्रांजिट कैम्प थाना पुलिस मौके पर आ गई और उसने ऐसा कर रहे पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुए ऐसा न करने की सख्त हिदायत दी साथ ही सभी चुनाव सामग्री को तत्काल हटा लेने को कहा।



रुद्रपुर। देर रात रम्पुरा क्षेत्र में कांग्रेस मेयर प्रत्याशी मोहन खेड़ा के भतीजे पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। जिसमें वह घायल हो गये उन्हें जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। घटना की सूचना पर तमाम कांग्रेस जिला अस्पताल पहुंच गये। बाद में पुलिस ने मामला शांत कराया। बताया गया है कि कांग्रेस मेयर प्रत्याशी मोहन खेड़ा का भतीजा विवेक खेड़ा देर रात करीब साढ़े 11 बजे कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए रम्पुरा गया था। आरोप है कि इस बीच भाजपा के कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और उसके साथ मारपीट की जिसमें वह घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। सूचना पर मोहन खेड़ा समेत तमाम कांग्रेसी जिला अस्पताल पहुंच गये। कांग्रेसियों ने हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बाद में पुलिस ने पहुंचकर मामला शांत कराया। समाचार लिखने तक मामले में तहरीर नहीं सौंपी गयी थी।



रामनगर (उद संवाददाता)। निकाय चुनाव को लेकर रामनगर में भी अपने निर्धारित समय पर मतदान का कार्य शुरू किया गया मतदान को लेकर सुबह से ही मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। अपना वोट डालने के लिए लाइनों में खड़े होकर इंतजार करते रहे तो वही रामनगर के कई मतदान स्थलों पर मतदान ड्यूटी में लगे कर्मचारियों द्वारा धीमी गति से मतदान कराए जाने की शिकायत विभिन्न प्रत्याशियों एवं मतदाताओं द्वारा अधिकारियों से की गई धीमी गति से हो रहे मतदान को लेकर कई मतदाता मतदान स्थल से भी वापस होते दिखाई दिए।

इसके अलावा कुछ मतदान स्थलों पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र तक जाने के लिए व्हीलचेयर उपलब्ध



न होने पर विकलांग मतदाताओं ने अपनी शिकायत मतदान स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे चुनाव प्रेक्षक



सर के सामने रखी ताओं का कहना था कि होने के साथ ही बुजुर्ग से मतदाताओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं की लेकर चुनाव प्रेक्षक



मोहम्मद नासिर ने बताया कि मतदान
में तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को
दिए गए हैं इसके अलावा जो विकलांग



मतदाताओं की शिकायत है उसकी
असुविधाओं से लेते हुए रिटनिंग ऑफिसर
राहुल शाह को निर्देश दिए गए हैं।